



www.wagadsandesh.com

वागड़ संदेश

Total Code RA.HIN27802

सम्पर्क

ई पेपर में खबरें व विज्ञापन के लिये सम्पर्क करें
E-mail: editor.wagadsandesh@gmail.com

8890633631

9309255545

6351581818

जन मन की आवाज

वर्ष-1 अंक-289

सागवाड़ा, सोमवार, 11 जुलाई, 2022

अवधि: हिन्दी ई-पेपर

पृष्ठ-1, मूल्य-10 रु. (वार्षिक)

जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की रखी मांग

जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने एडीएम को दिया राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन

डूंगरपुर। जिले में जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन डूंगरपुर ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने व उसे लागू करने की मांग की गई है। डूंगरपुर जिले में विश्व जनसंख्या दिवस पर डूंगरपुर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के

जिला अध्यक्ष रमेश जैन के नेतृत्व में फाउंडेशन के कार्यकर्ता आज कलेक्टर पर एकत्रित हुए। वहीं इसके बाद जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने देश में जनसंख्या कानून बनाने और लागू करने की मांग की गई है। इस मौके पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिला

अध्यक्ष रमेश जैन ने बताया की देश की आबादी काफी तेजी से बढ़ी है और देश के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की आबादी के अनुपात में भारत की आबादी एक अरब 40 करोड़ की जगह केवल 20 करोड़ होनी चाहिए थी। वहीं देश में प्राकृतिक संसाधन भी उसी अनुपात में थे। लेकिन आबादी हद से ज्यादा होने के कारण संसाधन खत्म होने के कगार पर है ऐसे में देश में जनसंख्या को नियंत्रित

करने वाले कानून बनाए जाने की जरूरत है। उन्होंने बताया की इसको लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन साल 2018 से संघर्ष कर रहा है। आज जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने और उसे पूरे देश में बिना जाती भेद के लागू करने की मांग को लेकर अतिरिक्त कलेक्टर को राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।

गरपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाएं और होगी बेहतर, मेडिकल कॉलेज को मिले 33 स्पेशलिस्ट डॉक्टर

डूंगरपुर। जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होगी। राजमेस की ओर से प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 300 डॉक्टरों की नई नियुक्ति की गई है। इसमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को 33 डॉक्टर मिले हैं। ये सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। इसमें 1 प्रोफेसर समेत 32 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सभी डॉक्टर को 15 दिन में ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के आने से डूंगरपुर में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। वहीं मरीजों को भी समय पर इलाज मिलेगा। डूंगरपुर जिलेवासियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में खुशखबरी आई है।

डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. महेंद्र डामोर ने बताया की हाल ही में राजमेस की ओर से मेडिकल कॉलेजों के लिए 300 डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। जिसमें डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को 33 डॉक्टर मिले हैं। 33 में से 1 प्रोफेसर की नियुक्ति की गई है। दंत रोग में प्रोफेसर डॉ. वीरेंद्रसिंह को डूंगरपुर नियुक्ति दी है। इसके अलावा 32 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जिन्हें अलग अलग 14 डिपार्टमेंट में नियुक्ति दी गई है। राजमेस की ओर से सभी डॉक्टर को 15 दिन में ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उनकी नियुक्ति निरस्त मानी जायेगी। इतने डिपार्टमेंट में इतने असिस्टेंट प्रोफेसर आए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. महेंद्र डामोर ने बताया की राजमेस की ओर से 33 डॉक्टरों को अलग-अलग डिपार्टमेंट में नियुक्ति दी गई है।

उन्होंने बताया की इसमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट में एक, फिजियोलॉजी में 2, बायोकेमिस्ट्री में एक, माइक्रो बायोलॉजी में दो, मनोरोग में एक, जनरल सर्जरी में 4 डॉक्टरों को नियुक्ति दी गई है।



सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नए संसद भवन' की छत पर भारत की एक विशाल राष्ट्रीय प्रतीक, 'अशोक स्तंभ' का अनावरण किया है। नए संसद भवन पर लगे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ 9,500 किलोग्राम कांस्य से बनाया गया है। और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है।

जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा करते 14 लोग गिरफ्तार, बिछीवाड़ा क्षेत्र में 5 अलग अलग केस में हुई गिरफ्तारी

डूंगरपुर। बारिश के बाद अब खेतीबाड़ी शुरू हो गई है। किसान खेतों में जुट गए हैं। वहीं खेती की जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ों के केस में भी बढ़ोतरी हुई है। बिछीवाड़ा पुलिस ने जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा करते 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी 5 अलग अलग केस में गिरफ्तार हुए हैं। बिछीवाड़ा थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया की बारिश के बाद जमीन विवाद के केस आ रहे हैं। थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों से ऐसी पांच सूचनाएं मिली, जिसमें दो पक्ष जमीन के विवाद में आमने-सामने होकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। एसआई प्रभुलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम वहां पहुंची। दोनों पक्षों

के बीच लड़ाई को शांत करवाया। वहीं अशांति फैलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी ने बताया की मामले में थावरचंद पुत्र खातू भगोरा मीणा निवासी बोखला, रामा पुत्र धनजी अहारी, रमेश पुत्र रामा अहारी, नरसी पुत्र रामा अहारी, काउवा पुत्र रामा अहारी, रामजी पुत्र पनजी अहारी, सोमा पुत्र शंकर अहारी, जीवा पुत्र वेसात कटारा, शक पुत्र थावरा अहारी, शांति पुत्र खातू भगोरा, सुरेंद्र पुत्र हलिया भगोरा निवासी बोखला, अशोक पुत्र रूपा कलासुआ निवासी पालपादर, बीरबल पुत्र शंकर डोण निवासी आमझरा और नाथू पुत्र शंकर डोण निवासी आमझरा को गिरफ्तार कर लिया है।

गड़ा वेजणिया पंचायत की सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास

सागवाड़ा। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा पंचायत समिति में गड़ा वेजणिया पंचायत की सरपंच रीना खांट के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव सोमवार को पास हो गया। आपसी मनमुटाव के कारण असंतुष्ट वार्ड पंच मिलकर सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। 21 जून को जिला परिषद डूंगरपुर में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। सोमवार को पंचायत मुख्यालय पर पुलिस बल की मौजूदगी में मतदान हुआ 6 में से 5 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े। सरपंच सहित कुल 6 सदस्य थे जिसमें पांच मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में गिरे। मतगणना के बाद प्राधिकृत अधिकारी मयूर शर्मा ने अविश्वास प्रस्ताव पास होने की



घोषणा कर सरपंच का पद रिक्त घोषित कर दिया। इस दौरान सागवाड़ा थानाधिकारी शैलेन्द्र सिंह सहित ओबरी, वरदा और चितरी थानाधिकारी भी मौजूद थे। सरपंच और वार्ड पंचों के आपसी मनमुटाव से चली गई सरपंच

की कुर्सी प्राप्त जानकारी के अनुसार सरपंच रीना खांट और वार्ड पंचों के बीच पिछले लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। सरपंच पर आरोप था कि वो वार्ड पंचों को तक्कों नहीं देती हैं और उनके काम भी नहीं हो रहे। मन मर्जी से कार्य करते थे। आमजन के भी कार्य नहीं हो रहे थे साथ ही वार्ड पंचों पर आरोप था कि दबाव बना कर प्रस्तावों पर साइन करवाते थे। इससे नाराज होकर वार्ड पंचों ने पिछले दिनों सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जिला परिषद में पेश किया था।

जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग



सोमलवाड़ा। प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन बैर तले मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम महेश गगोरिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि बढ़ती आबादी से संसाधन सीमित होने के साथ बेरोजगारी एवं महंगाई की भी बढ़ रही है बढ़ता प्रदूषण, अतिक्रमण पर रोक लगाना मुश्किल होता जा रहा है। जनसंख्या का बढ़ना देश के विकास में बाधा हो रही है। भू भाग छोटे पड़ रहे हैं। जीव जंतुओं की जातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। बताया कि बढ़ती जनसंख्या कम होते संसाधन बढ़ता प्रदूषण बेरोजगारी अपराध महामारी विकास को निगल रही है। बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए राज्य में पंचायती राज एवं नगर पालिका तथा सरकारी सेवाओं में लाभ 1995 को दो बच्चों का पुराना कानून को खत्म कर नए सिरे से 2022 से राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की आवश्यकता है। जाति, धर्म, संप्रदाय के बंधनों से ऊपर उठकर दो बच्चों का कानून लागू करने, तीसरी संतान उत्पत्ति होने पर सरकारी सहायता, अनुदान से पृथक करने एवं कानून तोड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं प्रथक करने व मताधिकार से वंचित रखने साथ ही चौथी संतान उत्पत्ति होने पर माता पिता को जेल भेजने का कानून लागू करने की मांग की है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जिला संरक्षक प्रकाश पंड्या, जिला महामंत्री दिनेश चंद्र पंड्या, उपशाखा अध्यक्ष गोवर्धन लाल पाटीदार, भाजपा जिला महामंत्री नानुराम परमार, भारतीय किसान मोर्चा ब्लॉक अध्यक्ष अमृत लाल पाटीदार, दिनेश पंड्या, भाजयुमो जिला अध्यक्ष कल्पेश भारती, देवेन्द्र सिंह, मोहनलाल यादव, भंवरलाल कलासुआ, एसटी मोर्चा खातू राम रोट, महावीर ननोमा, अनिल गरासिया, जयेश पंड्या, धनेश्वर पाटीदार, गजानंद भट्ट, चंद्रवीर सिंह चौहान, जयेश पंड्या, आशीष त्रिवेदी, गोविंद अहारी, हर्षद पंड्या, योगेश दर्जा, देवेन्द्र दर्जा, जयेश वसीटा, पृथ्वी नाई, चंद्रकांत पाटीदार सहित बड़ी संख्या में मौजूद रहे।



सागवाड़ा। डूंगरपुर मार्ग पर हाईवे निर्माण के दौरान लोडेश्वर डेम से सागवाड़ा शहर की ओर आ रही पानी की 350 एमएम पाइप लाइन टूट गई। सोमवार रात मरम्मत कार्य होने के कारण सागवाड़ा शहर की कल सुबह की पेयजल व्यवस्था बाधित रहने की संभावना है। ये जानकारी जलदाय विभाग सागवाड़ा ने दी।

स्कूलों के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की हो भर्ती

सोमलवाड़ा। राज्य के सरकारी प्रावि, उपावि तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नवीन पद स्वीकृत करने तथा पूर्व से स्वीकृत रिक्त पदों पर कर्मियों की भर्ती करवाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को पत्र भेजा। संगठन जिला अध्यक्ष बलवन्त बामणिया, जिला मंत्री दिलीप सिंह चौहान ने बताया कि विगत वर्षों में कई उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तथा प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं है।

भगवा रंग त्याग और समर्पण का निशान मानगढ़ धाम को लेकर बीटीपी के बयानों का भाजपा ने किया पलटवार

सोमलवाड़ा। वागड़ संत गोविंद गुरु की कर्म स्थली एवं इतिहास के पन्नों पर दर्ज अमर गाथा सैकड़ों जनजाति भक्त की शहीदों की शहादत की स्थली मानगढ़ धाम को लेकर गरमाई राजनीति को लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। 3 जुलाई को भाजपा द्वारा मानगढ़ धाम पर वाहन रैली के साथ राजनीतिक सभा का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का विरोध जताते हुए भारतीय ट्राइबल पार्टी ने शुद्धिकरण की बात कह कर राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीटीपी के बयानों का विरोध जताते हुए सोमवार को सोमलवाड़ा में भाजपा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं है।



राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाजपा जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि बीटीपी के नेताओं द्वारा शुद्धिकरण की बात का पलटवार भाजपा देना जानती है। बीटीपी मानगढ़ के इतिहास को नहीं जानती। उनका गैर जिम्मेदाराना बयान जारी हो रहा है जोकि समाज में भेद डालने वाला है। नानुराम परमार, खातूराम रोट महाराज, भंवर लाल कलासुआ, रतन लाल कलासुआ, अनिल गरासिया, लक्ष्मण डामोर, महावीर

ननोमा, गोविंद अहारी सहित ने अपने बयानों में कहा कि भाजपा ने हमेशा ही राष्ट्रीय मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय पहचान एवं विकास कार्य कराने की पहल की है, विकास कार्य भी करवाए हैं, जिसके बाद सत्ता में आई दूसरी सरकार ने विकास कार्य करवाए हैं। लेकिन बीटीपी के लोग इस पवित्र धाम को बदनाम करने में तुले हुए हैं, उनकी अंतर्गत टिप्पणियां समाज को स्वीकार नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारी संघ का सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी आन्दोलन काले कपड़े पहनकर कलेक्टर पर धरना देकर किया प्रदर्शन

डूंगरपुर। जिले के ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी आन्दोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज ग्राम विकास अधिकारियों ने काले कपड़े पहनकर कलेक्टर के बाहर धरना दिया। वहीं सरकार के खिलाफ अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार द्वारा किये गए वादों को याद दिलाया। ग्राम विकास अधिकारियों को लंबित मांगों पर लिखित समझौते के बाद भी मांगें पूरा नहीं किये जाने के विरोध में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा सरकार के खिलाफ वायदा खिलाफी आन्दोलन चलाया जा रहा है। आन्दोलन की इसी कड़ी में आज डूंगरपुर जिले में ग्राम विकास अधिकारी संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश के नेतृत्व में काले कपड़े पहनकर ग्राम विकास अधिकारी कलेक्टर पर एकत्रित हुए। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ कलेक्टर के बाहर धरना देते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

इस मौके पर संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश ने कहा की ग्राम विकास अधिकारी संघ की विभिन्न मांगों को लेकर 11 दिसम्बर 2021 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री के साथ समझौता हुआ था। जिसमें 30 से 45 दिनों में मांगों पर आदेश जारी करवाने का आश्वासन दिया था। लेकिन लिखित समझौते के 9 माह बीतने के बाद भी अभी तक उनकी मांगों को सरकार की ओर से अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में ग्राम विकास अधिकारियों को फिर से आन्दोलन की राह पकड़नी पड़ी है। इधर धरना प्रदर्शन के बाद ग्राम विकास अधिकारी संघ ने जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सरकार को लिखित समझौते को याद दिलाते हुए उनकी मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। वहीं मांगें पूरी नहीं करने पर आन्दोलन की कड़ी में 17 जुलाई को मंत्री, विधायक व विधायक प्रत्याशियों को ज्ञापन दिया जायेगा वहीं अगली कड़ी में 21 जुलाई को प्रदेश स्तर पर वादाखिलाफी आक्रोश दिवस मानते हुए प्रदर्शन किया जाएगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 आइटम बैन, इस्तेमाल और बेचने पर भी लगेगा जुर्माना

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर पालिकाध्यक्ष की व्यापारियों के साथ बैठक

सागवाड़ा। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर पूरे देश में 1 जुलाई से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसकी पालना हमें भी करनी है। हम सबको मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा कि हम हमारे शहर सागवाड़ा को कैसे साफ सुथरा रखें। यह बात नगरपालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया ने शहर के व्यापारियों की बैठक में रखी। सोमवार को नगरपालिका सागवाड़ा में एसडीएम रामचंद्र खटिक, तहसीलदार मयूर शर्मा और पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया की मौजूदगी में बैठक हुई जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे प्रतिबंध को लेकर चर्चा की गई। पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया ने कहा कि सागवाड़ा शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाये रखने में हर शहरवासी की अहम भागीदारी रही है। तहसीलदार मयूर शर्मा ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक कही पाया गया तो निश्चित तौर पर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने



कहा सिंगल यूज प्लास्टिक कितना हानिकारक है यह सबको पता है ऐसे में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करना बंद कर देवे। उपखंड अधिकारी द्वारा बताया की भारत सरकार द्वारा बंद सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम को किसी भी व्यापारी द्वारा बेचा जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तहसीलदार मयूर शर्मा द्वारा बताया की प्लाटिक से क्या क्या नुकसान

हो रहे है एवं भविष्य में इसके क्या दुष्परिणाम होंगे 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम जैसे इयरबड्स, गुब्बारे की प्लास्टिक डंडी, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी की प्लास्टिक डंडी, आइसक्रीम की प्लास्टिक डंडी, थर्मोकॉल के सजावटी सामान, प्लास्टिक की प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे पैक करने वाली पनी, इनविटेशन कार्ड पर लगाई जाने वाली पनी,

सिंगरेंट पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पनी, 100 माइक्रोन से पतले पीवीसी व प्लास्टिक के बैनर आदि शामिल हैं। नरेंद्र खोड़निया तहसीलदार एवं अधिशाषी अधिकारी मयूर शर्मा प्रतिपक्ष नेता हरीश सोमपुरा द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिबद्धित सिंगल यूज प्लास्टिक से बने जूनीस आइटमों की सूची का पेम्पलेट का विमोचन भी किया गया